चुनौतियों से जूझते हुए बीते संप्रग के दो साल

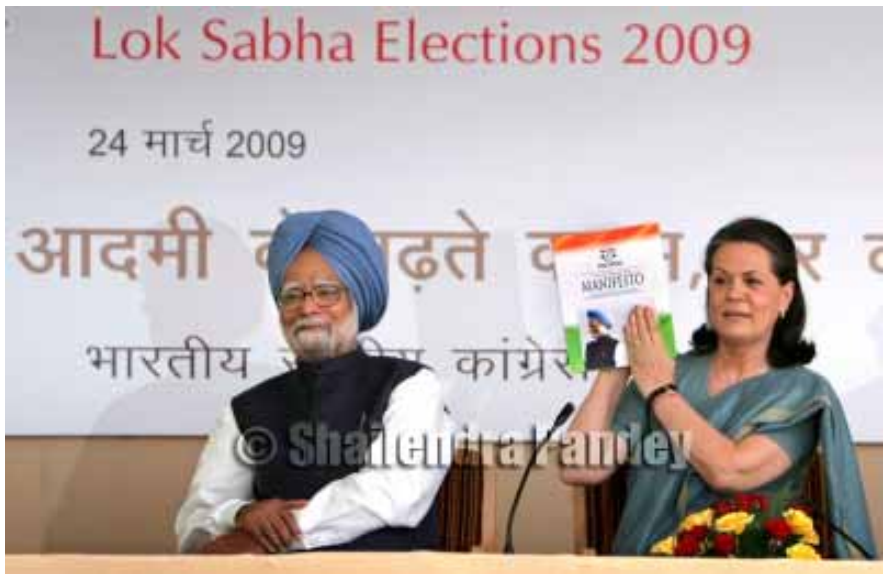

''भ्रष्टाचार के मुद्दों ने सरकार को बहुत परेशान किया और जन समुदाय को तब बड़ी हैरानी हुई थी जब उसने 'मिस्टर क्लीन' समझे जाने वाले मनमोहन सिंह को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गठबंधन मजबूरियों के चलते ऐसी स्थितियों के निर्मित होने का हवाला देते सुना था। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे लोगों पर कार्रवाई करने में दया नहीं बरती। 'देर है अंधेर नहीं' को चरितार्थ करते हुए सरकार ने चाहे वह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी हों, पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा हों या फिर अब सहयोगी दल द्रमुक के प्रमुख एम. करुणानिधि की बेटी कनिमोझी हों, सभी के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी और यह लोग इस समय तिहाड़ जेल में हैं।''

संप्रग-२ सरकार की दूसरी वर्षगांठ मनाते समय सत्तारुढ़ गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस जहां विभिन्न चुनौतियों से जूझ रही है वहीं उसके सहयोगी दलों के हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए संतोषजनक बात यह है कि उसके प्रधानमंत्री आज भी विभिन्न सर्वेक्षणों में मतदाताओं की पहली पसंद बने हुए हैं साथ ही पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन अन्य राष्ट्रीय दलों के मुकाबले बेहतरीन रहा है। इसके अलावा सरकार के तीसरे साल में प्रवेश के साथ ही कांग्रेस की चुनौतियां और बढ़ने के आसार हैं क्योंकि इस तीसरे साल में सरकार को विकास से जुड़े विभिन्न मोर्चों के अलावा राजनीतिक मोर्चे पर भी विजय हासिल करनी है।

संप्रग-२ सरकार के दूसरे वर्ष में विकास के मोर्चे पर भले काफी काम हुए हों लेकिन उनकी गूंज भ्रष्टाचार और महंगाई के शोर में दब कर रह गई। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही लेकिन यदि तथ्यों के लिहाज से देखें तो यह आरोप पूरी तरह से सही नहीं प्रतीत होते। देश के ढांचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ाना हो, अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी की गिरफ्त से बचाए रखने में सफल रहने के बाद उसे और गति प्रदान करना हो, विदेशी मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोत्तरी हासिल करना हो या फिर जीडीपी को एक खरब डॉलर तक पहुंचाना, सभी मामलों में सरकार कामयाब रही।

इस सरकार ने देश को शिक्षा का अधिकार कानून भी दिया लेकिन विवाद इस बात पर है कि इस कानून को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य कितना कितना खर्च उठाएंगे। इसके अलावा व्यापक जनाक्रोश के बाद सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून और लोकपाल विधेयक तैयार करने को भी बाध्य होना पड़ा है, ऐसी संभावना है कि यह दोनों विधेयक आगामी संसद सत्र में पेश किये जाएंगे। यदि यह दोनों विधेयक सर्वसम्मति से पास हो जाते हैं तो यह इस सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से होंगे। इसके अलावा सरकार ने आंतरिक मोर्चे पर भी काफी सक्रियता दिखाई और जम्मू-कश्मीर के लिए वार्ताकारों का एक दल नियुक्त किया। इस वार्ताकार दल ने राज्य में अमन चैन फिर स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अगले पांच साल में एक लाख युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल सिखाने की योजना को मंजूरी दी है जिसका सारा खर्च केंद्र उठाएगा। 'विशेष कौशल सशक्तिकरण और रोजगार योजना' के तहत युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाए जाएंगे ताकि वे रोजी रोजगार के लिए तैयार हो सकें। यह प्रयास यदि सफल रहा तो घाटी में अलगाव की भावना फैलाने वालों को निराशा ही हाथ लगेगी।

लेकिन इस सब के बावजूद संप्रग सरकार को उम्मीदों पर खरी उतरी भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कांग्रेस अब तक अपने चुनावी घोषणापत्र में किये गये वादों को पूरा नहीं कर सकी है। पार्टी ने चुनावों के समय कहा था कि वह सत्ता में आने के १०० दिनों के भीतर महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाएगी तथा शीघ्र ही खाद्य सुरक्षा कानून बनवाएगी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करवाएगी। इनमें महिला आरक्षण विधेयक १०० दिन की मियाद में पारित नहीं हो सका हालांकि सरकार ने इसे पारित करवाने के लिए जबरदस्त इच्छाशक्ति दिखाई लेकिन फिर भी आधा कदम ही आगे बढ़ सकी। अभी यह विधेयक राज्यसभा की ही मंजूरी पा चुका है, लोकसभा और देश की कम से कम आधी राज्य विधानसभाओं से इसे संस्तुति मिलना अभी बाकी है। इसके अलावा मनरेगा में भ्रष्टाचार की बात सरकार मानती तो है लेकिन इसे रोकने के प्रयास नाकाफी प्रतीत हो रहे हैं। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में भी मनरेगा को अभिनय प्रयोग बताते हुए इसके क्रियान्वयन में विभिन्न राज्यों में असमानता और भुगतान में अनियमितताएं जैसी बात कही गयी है।

सरकार पड़ोसियों और अन्य देशों से संबंध सुधारने में सफल रही लेकिन महंगाई और भ्रष्टाचार के मामले में तब असहाय-सी प्रतीत हुई जब कृषि और खाद्य मंत्री शरद पवार महंगाई बढ़ने की भविष्यवाणी करते रहे और भ्रष्टाचार के मामले प्याज के छिलकों की तरह एक एक कर सामने आते रहे। यकीनन प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के लिए सरकार का दूसरा वर्ष सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण रहा। पहले तो दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों में विलंब की खबरों से सरकार की किरकिरी हुई तो उसके बाद इस खेल आयोजन में हुए महा घोटाले ने सरकार के दामन पर दाग लगाये। विपक्ष ने इस मामले में सीधा पीएमओ को भी घसीटा। यही नहीं २जी स्पेक्ट्रम घोटाले ने तो संप्रग सरकार की लोकप्रियता को निचले स्तर पर पहुंचा दिया। इस मामले में विपक्ष की एकजुटता और एक पूरे संसद सत्र का हंगामे की भेंट चढ़ना सरकार की दुश्वारियों को और बढ़ाने के लिए काफी था। इस पर राहत की बजाय सरकार की मुश्किल तब और बढ़ गई जब सीवीसी पद पर पीजे थॉमस की नियुक्ति की गई। थॉमस के खिलाफ एक मामले में आरोपपत्र दाखिल है इसके बावजूद सीवीसी पद पर उनकी नियुक्ति को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया, मामला अदालत में गया और आखिरकार थॉमस की नियुक्ति अदालत ने खारिज कर दी। जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने संसद में इस मामले में अपनी गलती मानी। यही नहीं कालाधन तथा गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण आदि मामलों में सरकार को कई बार सर्वोच्च न्यायालय की फटकार सुनने को मिली।

इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर समाजसेवक अन्ना हजारे ने आमरण अनशन के माध्यम से सरकार के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिससे सरकार सकते में आ गई और उसे लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने में नागरिक समाज को भागीदार बनाने की बात माननी पड़ी। सीबीआई की कार्यप्रणाली और उसके कथित दुरुपयोग को लेकर भी सरकार अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष में विपक्ष के निशाने पर बनी रही।

यह सही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दों ने सरकार को बहुत परेशान किया और जन समुदाय को तब बड़ी हैरानी हुई थी जब उसने 'मिस्टर क्लीन' समझे जाने वाले मनमोहन सिंह को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गठबंधन मजबूरियों के चलते ऐसी स्थितियों के निर्मित होने का हवाला देते सुना था। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे लोगों पर कार्रवाई करने में दया नहीं बरती। 'देर है अंधेर नहीं' को चरितार्थ करते हुए सरकार ने चाहे वह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी हों, पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा हों या फिर अब सहयोगी दल द्रमुक के प्रमुख एम. करुणानिधि की बेटी कनिमोझी हों, सभी के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी और यह लोग इस समय तिहाड़ जेल में हैं।

संप्रग सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता वसंत साठे का यह कहना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्व रखता है कि 'गठबंधन का सिद्धांत कांग्रेस के लिए न केवल हास्यास्पद है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है क्योंकि यह संगठन को मजबूत बनाने के बजाय इसकी ऊर्जा को सोख लेता है।' साठे ने कहा है कि ममता बनर्जी, जयललिता और नीतीश कुमार जैसे क्षेत्रीय नेता बढ़ते जा रहे हैं और कांग्रेस समेत राष्ट्रीय दल कमजोर साबित हो रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस पहले गठबंधन सरकार की विरोधी रही लेकिन राजग के सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चलाने को देखते हुए उसने २००४ के चुनावों से पहले गठबंधन राजनीति को स्वीकार करते हुए गठबंधन बनाया।

इस गठबंधन की बदौलत वह लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता में आने में सफल भी रही लेकिन अब पार्टी को यह देखना चाहिए कि उसे उसके सहयोगियों ने मजबूत किया है या कमजोर। ममता बनर्जी की बात करें तो वह कांग्रेस की बात मानती नहीं बल्कि उससे अपनी बात मनवाती हैं। द्रमुक का भी विधानसभा चुनावों से पहले यही हाल था पर चुनावों में भारी पराजय के बाद अब वह बैकफुट पर है। लेकिन पार्टी ने अपने साथ ही तमिलनाडु में कांग्रेस को भी बैकफुट पर पहुंचा दिया है जहां द्रमुक प्रमुख के परिजनों के कारनामों की कीमत कांग्रेस को भी चुकानी पड़ी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भले चिरंजीवी की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया हो लेकिन इससे कांग्रेस को कोई विशेष फायदा नहीं होने जा रहा क्योंकि वहां बागी जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस के लिए भविष्य की बड़ी चुनौती की नींव डाल दी है। बिहार में राजद का साथ लेने से कांग्रेस का जो हश्र हुआ है उसकी भरपाई लंबे समय तक होनी मुश्किल नजर आ रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार की राकांपा से भले कांग्रेस का गठबंधन अच्छा चल रहा हो लेकिन महंगाई मुद्दे पर पवार की बयानबाजी और २जी घोटाले के आरोपी शाहिद बल्वा से उनके कथित संबंध कांग्रेस को भारी पड़ सकते हैं। साथ ही महाराष्ट्र में राकांपा के प्रभुत्व वाले एक सहकारी बैंक में सामने आई अनियमितताओं के बाद की गई कार्रवाई से दोनों दलों के रिश्तों में तल्खी महसूस की जा रही है।

बहरहाल, यह संप्रग सरकार के लिए अपनी उपलब्धियों को गिनाने और विफलताओं पर पार पाने का मौका है। संसद के बजट सत्र से पहले अपने मंत्रिमंडल में संक्षिप्त फेरबदल के समय जल्द ही बड़े फेरबदल का संकेत देने वाले प्रधानमंत्री अपनी सरकार को कैसी नयी छवि प्रदान करते हैं, और यह नयी छवि वाला मंत्रिमंडल जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा यह तो समय ही बताएगा लेकिन इतना तो है ही कि विपक्ष अपने हाथ में बहुत सारे सरकार विरोधी मुद्दों के होते हुए भी उसको सही तरह से घेरने में अब तक कामयाब नहीं हो सका है।